कविता

रुको बच्चो

- राजेश जोशी

(नीतीश के नशाबंदी वाले बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में नशे में धुत एक बोलेरो चालक ने सड़क पार कर रहे स्कूली बच्चों को कुचल दिया। इस त्रासद दुर्घटना में नौ बच्चों की मौत हो गयी और लगभग दस घायल बच्चों की हालत गम्भीर है। दुर्घटना को अंजाम देने वाली बोलेरो गाड़ी किसी भाजपा नेता की बताई जा रही है। इस दुःख में ही राजेश जोशी की एक कविता की याद आई- रुको बच्चों। संयोग है कि यह कविता बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई भी जाती है।)

रुको बच्चो रुको !
सड़क पार करने से पहले रुको
तेज रफ़्तार से जाती इन गाड़ियों को गुज़र जाने दो
वो जो सर्र से जाती सफ़ेद कार में गया
उस अफ़सर को कहीं पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है
वो बारह या कभी-कभी तो इसके बाद भी पहुँचता है अपने विभाग में
दिन, महीने या कभी-कभी तो बरसों लग जाते हैं
उसकी टेबिल पर रखी ज़रूरी फ़ाइल को खिसकने में

रुको बच्चो !
उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो
कौन पूछ सकता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज़ कार में
कितने मुक़दमे लंबित हैं तुम्हारी अदालत में कितने साल से
कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है
लेकिन नारा लगाने या सेमीनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य
कई बार तो पेशी दर पेशी चक्कर पर चक्कर काटते
ऊपर की अदालत तक पहुँच जाता है आदमी
और नहीं हो पाता इनकी अदालत का फ़ैसला

रुको बच्चो ! सडक पार करने से पहले रुको
उस पुलिस अफ़सर की बात तो बिल्कुल मत करो
वो पैदल चले या कार में
तेज़ चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है
यह और बात है कि जहाँ घटना घटती है
वहां पहुँचता है वो सबसे बाद में

रुको बच्चों रुको
साइरन बजाती इस गाड़ी के पीछे-पीछे
बहुत तेज़ गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार
नहीं, नहीं, उसे कहीं पहुँचने की कोई जल्दी नहीं
उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से उठने में लग जाते हैं कई मिनट
उसकी गाड़ी तो एक भय में भागी जाती है इतनी तेज़
सुरक्षा को एक अंधी रफ़्तार की दरकार है
रुको बच्चो !
इन्हें गुज़र जाने दो

इन्हें जल्दी जाना है
क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुँचना है

खुदा के लिए कह दो कि ये झूठ है.

- **विनीत सिंह**

क्या किसी घोटाले की हूबहू स्क्रिप्ट सालभर पहले लिखी जा सकती है... और लिख भी गई तो जांच एजेंसियां, बैंक और सरकार क्यों आंखें बंद किए बैठी थी... कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉ. कपिल देव शर्मा जी ने जब इन द नेम ऑफ गॉड पढ़ने को कहा तो हैरत के साथ ऐसे ही तमाम सवाल मन में कौंध उठे...

पहले पहल तो यकीन ही नहीं आया... लेकिन, दो दिन की छुट्टियां जब इस किताब पर कुर्बान की तो लगा कि हम एक खोपचे में बैठे सिर्फ वही देख और सुन रहे हैं जो हमें दिखाया और सुनाया जा रहा है... जबकि मुल्क में चल रही सियासत का सच बेहद डरावना और घिनौना है. किताब को पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज जो सामने आई उस पर शायद ही कोई यकीन कर पाए... भक्त तो बिल्कुल भी नहीं... और यह सच्चाई थी ... पंजाब नेशनल बैंक के महाघोटाले की वो स्क्रिप्ट जो दो रात मेरे हाथों में रही...

इस किताब में एक बैंक घोटाले का खुलासा किया गया है... पैरों तले जमीन तब खिसकी जब... इस घोटाले को अंजाम देने वाले मुख्य किरदार का नाम पढ़ा... नीरव चोकसी

पूरी कहानी बैंक घोटाले पर लिखी गई है... कहानी में नीरव चोकसी एक हीरा कारोबारी है, जो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बैंक में गड़बड़ी करता था. गलत तरीके से बैंक से पैसे जुटाता था और आखिरकार पैसा लेकर फरार हो जाता है... कहानी में किरदार की पहुंच को बॉलीवुड और हॉलीवुड तक बताया गया है...

अब सुनिए हकीकत... पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड के नाम थे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी... यानि किताब में लेखक ने इनमें से एक का नाम और दूसरे का सरनेम इस्तेमाल किया था... कहानी के माफिक ही नीरव मोदी ने बैंक से गड़बड़ी करके हजारों करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया... और उसका कारोबार भी कहानी की तरह हीरे का निकला...

सबसे ज्यादा हैरत तो तब हुई जब पूरी कहानी पढ़ने के बाद लेखक की जिंदगी पर गौर फरमाया... स्क्रिप्ट राइटर हैं रवि सुब्रमण्यन... पेशे से बैंकर...

अब सवाल उठना लाजमी था कि क्या कोई बैंकर घोटाले की इतनी सटीक स्क्रिप्ट लिख सकता है... हूबहू पीएनबी कांड जैसी... मेरी जितनी समझ है वह तो यही कहती है कि भाई इस महाघोटाले की खबर तमाम लोगों को थी... जिसमें से एक थे किताब के लेखक रवि सुब्रमण्यन...

और इससे भी बड़ा सवाल यह कि जब किसी घोटाले की पूर्व सूचना बाजार में खुलेआम बिक रही थी तो देश की जांच एजेंसियां, बैंक और सरकार आंख क्यों मूंदे हुए बैठी थी...

मतलब साफ है कि घोटाला आम आदमी की सोच से कई गुना बड़ा है और इसका दायरा सिर्फ नीरव मोदी या मेहुल चोकसी तक ही नहीं सिमटा हुआ... तमाम सफेदपोश इसका हिस्सा हैं.... अंत में

भारत भाग्य विधाताओं की जय...

खबर (दार) झरोखा

विकास नारायण राय

बच्चों की नृशंस हत्या पर इतना सन्नाटा क्यों, रहनुमा!

फिल्म स्टार श्रीदेवी की दुबई में अकाल मृत्यु भारतीय मीडिया में राष्ट्रीय शोक बनकर छायी रही है। राजनीति का तकाजा कहिये कि मोदी और राहुल जैसों ने भी ग्लैमर की दुनिया की इस मीडिया इवेंट पर ट्विटर के माध्यम से जुड़ने में तनिक देर नहीं की। इसी 20 जनवरी देश की राजधानी दिल्ली में सत्रह श्रमिक नियम-कानून ताक पर रख चलायी जा रही पटाखा फैक्ट्री में जल कर मर गए, तब ये ट्विटर खामोश थे। आज भी, बेशक सभी की संवेदनाओं का सम्मान करते हुए, क्या पूछना ठीक नहीं होगा कि दो अन्य बेहद हृदयविदारक हादसों पर हमारे तमाम रहनुमा हलकों में इतना सन्नाटा क्यों?

बिहार के मुजफ्फरपुर में बीस स्कूली बच्चों को एक शराबी ड्राइवर के बेकाबू तेज गति वाहन से कुचलने (अब तक 9 की मृत्यु) को महज सड़क दुर्घटना के खाते में नहीं डाला जा सकता। न अकेले दोषी मनोज बैठा को जिम्मेदार ठहरा कर इसका कानूनी पटाक्षेप संभव है। दरअसल, ये ऐसी नृशंस हत्याएं हैं, जिनकी जिम्मेदार नीतीश कुमार की शराबबंदी और नितिन गडकरी की ऑटो नीतियां हैं। वह राष्ट्रीय मीडिया भी जो इन नीतियों के लिए तालियाँ जुटाता रहा है।

हापुड़ के पिलखुआ में सात किशोर श्रमिक, आबादी से लगे रेल ट्रैक को पार करने में वहां से गुजरती ट्रेन की चपेट में आकर कट मरे। उस व्यापक इस्तेमाल में आने वाले शार्ट कट रास्ते पर न सुरक्षा फेंसिंग है, न चेतावनी व्यवस्था, न रोशनी, न सड़क और न संचालित रेल क्रासिंग। प्रधानमन्त्री मोदी के बुलेट ट्रेन की प्राथमिकता के चलते देश की ट्रेन पटरियों पर हजारों उपेक्षित रास्ते असुरक्षित रखे जाने की बाध्यता के शिकार हैं।

भारत ने सड़क यातायात को दुर्घटना रहित करने के नवम्बर 2015 के ब्रासीलिया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये हुए हैं, जिसके अनुसार सन 2020 तक दुर्घटनाओं और इनमें होने वाली मृत्यु को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि, सरकार की लागू सड़क परिवहन विस्तार नीतियों में मृत्यु दर में अंकुश लगाने वाली समुचित प्राथमिकताओं का शायद ही संकेत मिले। जहाँ 2006 में सड़क पर प्रति सौ दुर्घटना में 20.4 व्यक्तियों की मौत होती थी, 2015 में यह बढ़कर 26.3 पहुँच गयी।

हाल के वर्षों में प्रति वर्ष पांच लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गयी हैं। इनकी मुख्य वजह हैं, तेज रफ्तार वाहन और शराबी ड्राइवर. तेज रफ्तारी, सड़क पर होने वाली 48 प्रतिशत दुर्घटनाओं और 44 प्रतिशत मौतों के पीछे रहती है। दो पैर व दो पहिया वाहन इस्तेमाल करने वालों के लिए व्यस्त सड़क पर व्याप्त घोर अव्यवस्था भी मारक दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह है। उनके लिए अलग से फुटपाथ या ट्रैक न होना आम बात है। सड़क पार करने के लिए स्वचालित सीढ़ी और रैंप जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में नित चौड़े होते राजमार्गों पर तेज भागते वाहनों के बीच सड़क पार करना आत्मघात को निमंत्रण ही कहा जायेगा।

मुख्य मंत्री नितीश कुमार की बिहार राज्य में लागू की गयी पूर्ण शराबबंदी, जैसा कि चेताया गया था, एक पूरी तरह विफल कवायद बन चुकी है। मनोज बैठा जैसे लोग, दरअसल, कम समय में ज्यादा शराब गटकने के आदी हो रहे हैं। राज्य में तस्करी से आने वाली रेगुलर शराब के महंगी होने के कारण, अवैध शराब के उत्पादन में बेहद वृद्धि हुयी है। इसने राजनीतिक सत्ताधारियों, आबकारी और पुलिस कर्मियों, शराब तस्करों और छोटे-बड़े गुंडों के लिए, अघोषित समृद्धि का दरवाजा खोल दिया है।

एक तरह से, मुजफ्फरपुर प्रकरण में आने वाले समय के बिहार की तस्वीर देखी जा सकती है. सड़क हादसे उसके महज एक आयाम होंगे। 'पूर्ण शराबबंदी' पहल से नीतीश कुमार अपने लिए प्रधानमन्त्री पद के दावेदार का एक विशिष्ट स्वरूप गढ़ना चाहते थे। अगर वे इसी तरह शेर की सवारी की जिद पर कायम रहे तो बिहार के व्यापक माफियाकरण का श्रेय अवश्य ले जायेंगे।

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की छवि मीडिया ने एक कार्यकुशल विकास संचालक की बना रखी है. यह अकारण नहीं है। गडकरी ने विरासत में मिली हाई वे और हाई स्पीड नीति को यातायात विकास के मॉडल के रूप में और चमका रखा है। यहाँ तक कि तेज कारों की बढ़ती जनसंख्या के दबाव में, हाई वे बनाने की गति तीन गुना बढ़ाकर प्रतिदिन 30 किलोमीटर कर दी गयी है। बेशक, हाई वे पहले की तरह ही असुरक्षित बने रहें।

दरअसल, गडकरी के नेतृत्व में हाई वे और हाई स्पीड आयामों को एक दूसरे का सफल पूरक बना दिया गया है। दोनों आयाम जीडीपी गणना में भी शरीक किये जाते हैं। हाल में ग्रेटर नॉएडा में गडकरी की छत्र-छाया में संपन्न हुये ऑटो एक्सपो 2018 में प्रदर्शित, भविष्य की इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में ऐश-आराम के आकर्षण के साथ तीव्र गति का नुस्खा ही हावी दिखा। बाजार में उतरने के बाद ये गाड़ियां सिर्फ गडकरी के हाई वे पर ही तो नहीं दौड़ेगी। गाहे-बगाहे, मुजफ्फरपुर की तरह, छोटे-मोटे शहरों की सड़क पर भी बच्चे इन्हें लाये जाने की कीमत अपनी जान से चुकाते रहेंगे।

शायद किसी दिन कोई सड़क विज्ञानी हमें आज जैसी दीवानगी से बचा सके. विकास की और ग्लैमर की भी। वह चाहे तो और बातों के अलावा यह भी बताये कि मोदी की बुलेट ट्रेन और गडकरी की हाई स्पीड सड़क में से कौन अधिक घातक कही जायेगी? नीतीश की शराबबंदी उसके अध्ययन का जरूरी फुटनोट बनेगी ही! फिलहाल, मुजफ्फरपुर और हापुड़ के हादसों में शिकार परिवारों को सब की दिली संवेदना जरूर पहुंचे।

सबसे ज्यादा विकास कर रहे हैं गडकरी जी, सड़क से ही 13,457 करोड़!

इस सरकार में सबसे ज्यादा विकास गडकरी जी कर रहे हैं। मैं शारीरिक रूप से उनके आकार-प्रकार की नहीं, बल्कि उनके परिवहन विभाग, खासकर सड़क विभाग को मिल रहे सरकारी धन की बात कर रहा हूं। इस बार के बजट में उनके सड़क विभाग का आवंटन सबसे ज्यादा बढ़ाकर 1,34,572 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

यह सारे के सारे बजट आवंटन का 5.51 प्रतिशत है, जबकि चालू वित्त वर्ष 2017-18 में यह 1,07,092 करोड़ रुपए के साथ कुल बजट आवंटन का 4.83 प्रतिशत रखा गया था। असल में विकास का सीधा-सा समीकरण है, जितना ज्यादा विकास, उतना ज्यादा कमीशन।

गडकरी जी भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन इस समय पार्टी के लिए धन जुटाने की मुख्य जिम्मेदारी उनकी है। इसीलिए गोवा से लेकर मणिपुर तक में जहां भी विधायक खरीदने होते हैं, गडकरी जी निजी प्लेन से वहां पहुंच जाते हैं। गुजरात के आदर्श मॉडल में किसी भी सरकारी योजना में 10 प्रतिशत कट आराम से चलता है। वे 15 प्रतिशत से ऊपर नहीं जाते। अन्यथा दूसरे दलों और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा!

इस बार सोचिए अगर गडकरी जी ने सड़क पर सारे 1,34,572 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए तो सीधे-सीधे 10 प्रतिशत कट का 13,457 करोड़ रुपए पार्टी फंड में तो आ ही जाएगा। बाकी 2019 के लोकसभा चुनावों के कम से कम 50,000 करोड़ रुपए के खर्च का इंतज़ाम करने के लिए बड़े शाह साहब तो अभी से लगे ही हुए हैं।